भारत-साइप्रस: “व्यापक” से “रणनीतिक” साझेदारी

अंतरराष्ट्रीय संबंध | समाचार संदर्भ: भारत-साइप्रस रणनीतिक साझेदारी, 22 मई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

किसी द्विपक्षीय संबंध को “रणनीतिक साझेदारी” कहने का अर्थ है कि दोनों देश राजनीतिक संवाद, रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को एक साथ आगे बढ़ाने का औपचारिक इरादा जताते हैं। साझा वक्तव्य कानूनी संधि नहीं होता; वह दोनों सरकारों की घोषित प्राथमिकताओं का दस्तावेज़ है। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर का यूरोपीय संघ का सदस्य द्वीप-देश है, और यात्रा के समय उसके पास यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता थी।

खबरों में क्यों

साझा वक्तव्य (PIB, 22 मई 2026) के अनुसार साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडूलिडीस 20 से 23 मई 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। 22 मई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने मौजूदा व्यापक साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने पर सहमति जताई।

मुख्य अवधारणा: साझा वक्तव्य में “स्वागत” और “सहमति” का फ़र्क़

साझा वक्तव्य में कुछ बातें हो चुकी हैं (जैसे समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर), कुछ शुरू करने पर सहमति है (जैसे सामाजिक सुरक्षा समझौते की वार्ता) और कुछ केवल “तलाशने” या “प्रोत्साहित करने” की इच्छा है (जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की संभावना)। परीक्षा-उत्तर में इन तीनों को अलग लिखें, वरना इरादे को उपलब्धि समझने की भूल होती है।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

यात्रा	**साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडूलिडीस की राजकीय यात्रा, 20-23 मई 2026; द्विपक्षीय वार्ता नई दिल्ली में 22 मई 2026 (साझा वक्तव्य)**
संबंधों का स्तर	नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापक साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने पर सहमति जताई। 2025 में प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा के समय संयुक्त कार्य योजना 2025-2029 घोषित हुई थी।
हस्ताक्षरित (वक्तव्य में स्वागत)	आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह पर समझौता-ज्ञापन; खोज और बचाव समन्वय पर तकनीकी व्यवस्था; साइप्रस रक्षा-अंतरिक्ष उद्योग क्लस्टर और भारतीय रक्षा निर्माता संघ (SIDM) के बीच समझौता-ज्ञापन; नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान, राजनयिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक सहयोग तथा ICAI-ICPAC के बीच समझौता-ज्ञापन।
रक्षा	2026-2031 के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग रोडमैप संपन्न; फ़रवरी 2026 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग कार्यक्रम का स्वागत। नौसैनिक जहाज़ों की नियमित पोर्ट कॉल और संयुक्त प्रशिक्षण को "प्रोत्साहित" करने की बात।
आगे की वार्ता	प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर वार्ता जारी रखना; सामाजिक सुरक्षा समझौते की वार्ता "जल्द से जल्द" शुरू करना; द्विपक्षीय संपर्क संवाद पर चर्चा।
भुगतान और कनेक्टिविटी	भारत की UPI और यूरोपीय केंद्रीय बैंक की TIPS प्रणाली के बीच अंतर-संचालन का ढाँचा बनने का स्वागत किया गया।
बहुपक्षीय रुख़	साइप्रस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन दोहराया। भारत ने साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन दोहराया और संयुक्त राष्ट्र के ढाँचे में द्विक्षेत्रीय, द्विसामुदायिक महासंघ आधारित समाधान की बात कही।
अन्य मंच	साइप्रस के हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) में शामिल होने की सराहना; आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचा गठबंधन (CDRI) में शामिल होने की रुचि का स्वागत; भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) की संभावना पर सहमति।

साझेदारी के चार आधार

राजनीतिक और बहुपक्षीय: दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में एक-दूसरे का समर्थन और उम्मीदवारियों में सहयोग की बात करते हैं। साइप्रस प्रश्न पर भारत का रुख़ वक्तव्य में दर्ज है।

सुरक्षा और रक्षा: आतंकवाद-रोधी कार्य समूह, साइबर सुरक्षा संवाद, रक्षा उद्योग सहयोग और 2026-2031 का रोडमैप। इनके पूरे पाठ हमने नहीं पढ़े; हम केवल वक्तव्य में दिए गए वर्णन पर निर्भर हैं।

अर्थव्यवस्था और समुद्री सहयोग: वक्तव्य साइप्रस को यूरोप का समुद्री प्रवेश-द्वार बताता है, जहाँ पारगमन, भंडारण और रसद का केंद्र बनने की संभावना जताई गई है। मुंबई में भारत-साइप्रस व्यापार मंच हुआ और भारत-ग्रीस-साइप्रस व्यापार और निवेश परिषद के गठन की सराहना की गई।

लोग और कौशल: शिक्षा, राजनयिक प्रशिक्षण, संस्कृति, पर्यटन और कांसुलर संवाद। प्रवासन समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता अभी वार्ता के चरण में हैं।

यह विषय क्यों मायने रखता है

यूरोपीय संघ का रास्ता: वक्तव्य में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का उल्लेख है, जिसके बारे में कहा गया कि वह 27 जनवरी 2026 के शिखर सम्मेलन में संपन्न हुआ और नेताओं ने उसके शीघ्र हस्ताक्षर और कार्यान्वयन का आग्रह किया। यह वक्तव्य की भाषा है; समझौते की वर्तमान स्थिति हमने अलग से नहीं जाँची।

पूर्वी भूमध्य सागर और IMEEC: वक्तव्य भारत से पश्चिम एशिया होकर यूरोप तक कनेक्टिविटी की बात करता है। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति इसी कारण रणनीतिक मानी गई है, यह वक्तव्य का तर्क है।

बहस के बिंदु और सावधानियाँ

घोषणा और क्रियान्वयन: साझा वक्तव्य इरादे और प्रक्रियाएँ दर्ज करता है। मसलन आतंकवाद-रोधी कार्य समूह की पहली बैठक "जितनी जल्दी हो सके" होनी है; वह हुई या नहीं, हमने नहीं जाँचा।

एकतरफ़ा स्रोत: यह सरकारी साझा वक्तव्य है। उसमें कोई व्यापार आँकड़ा या वित्तीय राशि नहीं है, इसलिए हमने कोई आँकड़ा नहीं दिया। निवेश के बारे में वक्तव्य केवल इतना कहता है कि साइप्रस भारत में निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

स्रोत और सीमाएँ: हमने केवल यह साझा वक्तव्य पढ़ा (https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2264380&lang=1&reg=3)। समझौता-ज्ञापनों के पाठ, साइप्रस सरकार के बयान और यात्रा के बाद की प्रगति हमने नहीं देखी।

पूर्व लेख से अंतर: pcsmantra.com पर साइप्रस के नाम से हमें कोई लेख नहीं मिला (खोज: "साइप्रस", "Cyprus")।

आगे की राह

इस लेख को 22 मई 2026 के साझा वक्तव्य की स्थिति मानें। वक्तव्य में आगे की तारीख़ें (जैसे जुलाई में भारत-EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठक, 2027 में 65वीं वर्षगाँठ) बीत चुकी या आने वाली हो सकती हैं; हमने उनका परिणाम नहीं जाँचा।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) हस्ताक्षरित दस्तावेज़ और संपन्न रोडमैप; (2) वार्ता शुरू करने की सहमति; (3) "प्रोत्साहित करने" या "तलाशने" जैसे इरादे; और (4) हमारी व्याख्याएँ।

मेंस दृष्टि

GS-II: भारत और उसके पड़ोस के बाहर के देशों से द्विपक्षीय संबंध, भारत के हितों पर विदेशी नीतियों का प्रभाव। उत्तर में हस्ताक्षरित, वार्ताधीन और इच्छा-स्तर की बातें अलग लिखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

भारत-साइप्रस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने के महत्व का परीक्षण कीजिए। साझा वक्तव्य में हस्ताक्षरित और वार्ताधीन बातों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: यात्रा और उन्नयन।

मुख्य भाग में: हस्ताक्षरित बनाम वार्ताधीन; रक्षा, समुद्री और आर्थिक आयाम; यूरोपीय संघ और IMEEC; सीमाएँ।

निष्कर्ष में: रणनीतिक साझेदारी के रक्षा, समुद्री और आर्थिक अवसरों को यूरोपीय संघ तथा IMEEC के संदर्भ में परखें; हस्ताक्षरित दस्तावेज़, वार्ताधीन समझौते और भविष्य की बैठकों को अलग रखते हुए घोषणा को पूरा क्रियान्वयन न मानें।

स्रोत

- PIB, साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा पर साझा वक्तव्य (22 मई 2026)

सभी तथ्य इस एक सरकारी साझा वक्तव्य से हैं, जो दोनों सरकारों का साझा पक्ष है।

याद रखें: साझा वक्तव्य के अनुसार 22 मई 2026 को भारत और साइप्रस ने व्यापक साझेदारी को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने पर सहमति जताई, कई समझौता-ज्ञापनों का स्वागत किया और रक्षा रोडमैप 2026-2031 को संपन्न बताया। प्रवासन और सामाजिक सुरक्षा समझौते अभी वार्ता में हैं।